

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 441] नई दिल्ली, बुधवार, अश्विन 5, 1972/आश्विन 13, 1894

No. 441] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 1972/ASVINA 13, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 5th October 1972

S.O. 641(E)/18A/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of the opinion that Rampooria Cotton Mills Limited, Serampore, P.O. Rishra (District Hooghly), an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the following body of persons:—

Chairman

1. Shri A. Bose, Special Officer and *ex-officio* Secretary to the Government of West Bengal, Department of Closed and Sick Industries, Calcutta

Members

2. Shri S. C. Chakravarti, I.A.S. (Retired),

3. Shri M. M. Sanyal, Commercial Accountant, Directorate of Labour, West Bengal.

(hereinafter referred to as the authorised body of persons) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, Rampooria Cotton Mills Limited, Serampore, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (i) the authorised body of persons shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;
- (ii) the authorised body of persons shall hold office for five years from the date of publication of this order in the Official Gazette;
- (iii) the Central Government may terminate the appointment of the authorised body of persons earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F. 3/37/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1972

का० प्रा० 641(अ)/18ए/आई० डी० प्रार० ए०/72.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि रामपुरिया काटन मिल्स लिमिटेड, सीरम्पूर, हाकधर गिश्वा (जिला हुगली), औद्योगिक उपक्रम का जिसकी बाबत उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन अन्वेषण किया जा चुका है, प्रबन्ध इस रिति से किया जा रहा है कि लोक हित में अति अहितकर है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियों,

1. श्री ए० बोर

अध्यक्ष

विशेष अधिकारी और पदेन मन्त्रि

पश्चिम बंगाल सरकार, बन्द

और अवस्थित उद्योग विभाग, कलकत्ता ।

2. श्री एम० सी० चक्रवर्ती,

सदस्य

आई० ए० एस० (सेवा-निवृत्त)

3. श्री एम० एम० संयाल,

सदस्य

वाणिज्यिक लेखापाल, श्रम निदेशालय,

पश्चिम बंगाल ।

के निकाय को (जिसे इस में उसके पश्चात प्राधिकृत व्यक्तियों का निकाय कहा गया है) उक्त उपक्रम अथवा रामपुरिया काटन मिल्स लिमिटेड, सीरमपुर का पूर्ण प्रबन्ध निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए ग्रहण करने के लिए पत्रद्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

- (i) प्राधिकृत व्यक्तियों का निकाय केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए सभी निर्देशों का पालन करेगा ;
 - (ii) प्राधिकृत व्यक्तियों का निकाय राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष के लिए पदामीन रहेगा ;
 - (iii) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकृत व्यक्तियों के निकाय को नियुक्ति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, पहले ही समाप्त कर सकेगी ।
2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा ।

[सं० फा० 3/37/72-सी० यू० सी०]

के० एम० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

